बजट सत्र

दंतेवाड़ा-बस्तर में अवैध कटाई के 6 सौ मामले

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। वन मंत्री विक्रम उसेंडी ने विधानसभा में बताया कि दंतेवाड़ा एवं बस्तर क्षेत्र में अवैध वन कटाई के 6 सौ से ज्यादा मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। इनमें 49 लाख से ज्यादा के लकड़ी जब्त की गई है एवं तीन वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन हैं।

भाजपा सदस्य भीमा मंडावी एवं संतोष बाफना के अलग-अलग प्रश्नों के जवाब में श्री उसेंडी ने यह जानकारी दी। श्री मंडावी के प्रश्नों के जवाब में श्री उसेंडी ने बताया कि दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2008 से 31 मई 2009 के बीच अवैध वन कटाई के 299 मामले दर्ज किए गए। इनमें दंतेवाड़ा परिक्षेत्र में 126, गीदम परिक्षेत्र में 92, बचेली परिक्षेत्र में 77, बारसूर परिक्षेत्र में 4 प्रकरण शामिल हैं।

वन मंत्री ने बताया कि उपरोक्त मामलों में से अब तक कुल 57 मामलों में 50 हजार 996 रुपए मावजा/महसूल की राशि वसूल की जा चुकी है। अभी तक कोई वाहन राजसात नहीं किया गया है। लेकिन 3 वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

भाजपा सदस्य संतोष बाफना के प्रश्नों के जवाब में श्री उसेंडी ने बताया कि बस्तर वन मंडल के जगदलपुर परिक्षेत्र में वर्ष 2009 में अवैध वन कटाई के 90 मामले दर्ज किए गए। इनमें 29.91 घन मीटर काष्ठ कीमत 2 लाख 60 हजार, 18 नग बल्ली एवं 12 हजार रुपए की 99 क्विंटल जलाऊ लकड़ी जब्त की गई। इसी तरह माचकोट परिक्षेत्र में अवैध वन कटाई के 222 मामले इसी दौरान दर्ज किए गए।

इसमें 313 घन मीटर काष्ठ कीमत 45 लाख 50 हजार, 2205 नग बल्ली कीमत 1 लाख 45 हजार एवं 3 हजार मूल्य की 24 क्विंटल जलाई लकड़ी जब्त की गई।

7 आईएफएस के खिलाफ विभागीय जांच

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। वन मंत्री विक्रम उसेंडी ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में भारतीय वन सेवा के 125 अफसर कार्यरत हैं। इनमें से 13 अधिकारी दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय वन सेवा के 7 अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जबकि 2 अफसरों के खिलाफ मामले ईओडब्ल्यू में दर्ज हैं।

2 के मामले ईओडब्ल्यू में

कांग्रेस सदस्य शिव कुमार डहरिया के प्रश्नों के लिखित जवाब में श्री उसेंडी ने बताया कि जो आईएफएस दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं उनमें प्रदीप कुमार पंत 2006 से, आर.के. सिंह नवंबर 2006 से, के. सुब्रमणियम दिसंबर 2003 से कौशलेन्द्र सिंह 2007 से, आर.के. गोवर्धन अक्टूबर 2006 से, संजय शुक्ला फरवरी 2004 से, पी.वी. नरसिम्हा राव नवंबर 2008 से, पी.सी. पांडे अक्टूबर 2009 से, देवाशीष दास मई 2006 से, एस.एस. बजाज नवंबर 2004 से, सुधीर अग्रवाल अक्टूबर 2005 से, यूनूस अली अगस्त 2008 से एवं आलोक कटियार सितंबर 2008 से, शामिल हैं।

वन मंत्री ने बताया कि 7 आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ वर्तमान में विभागीय जांच लंबित है। इनमें एस.सी. रहटगांवकर, राकेश चतुर्वेदी, एस.एस.डी. बड़गैय्या, वी. श्रीनिवासराव, अमरनाथ प्रसाद, हेमंत कुमार पांडेय एवं एस.के. पैकरा शामिल हैं। श्री उसेंडी ने बताया कि 2 आईएफएस अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में भी प्रकरण लंबित है इनमें वी.एस. ध्रुव एवं जे.एस. कैलासिया शामिल हैं।

पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण पर डेढ़ करोड़ खर्च

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए पिछले दो वर्षों में लगभग डेढ़ करोड़ की राशि खर्च की गई।

भाजपा सदस्य जगेश्वर भगत के प्रश्नों के लिखित जवाब में श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में सांस्कृति धरोहर के रूप में पिछले दो वर्षों में किसी भी पुरातात्विक महत्व के स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया गया है। पूर्व से मान्य धरोहरों के संरक्षण के लिए वर्ष 2008-09 में 84 लाख 73 हजार एवं 2009-10 में 59 लाख 53 हजार की राशि खर्च की गई।

श्री अग्रवाल ने बताया कि जशपुर जिले में मान्य एवं संरक्षण योग्य स्मारक स्थल प्रस्तावित नहीं है। जांजगीर-चांपा जिले में लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद राज्य संरक्षित स्मारक है और विष्णु मंदिर जांजगीर इंदर देऊल खरौद, सबरी मंदिर, चंद्रचूड मंदिर और केशव नारायण मंदिर शिवरीनारायण, प्राचीन मंदिर अड़भार केंद्र संरक्षित स्मारक है। वर्तमान में संरक्षण हेतु स्थल प्रस्तावित नहीं है।

2 सालों में ढाई हजार विदेशी पर्यटक आए

प्रदेश को 26 लाख से ज्यादा की आय

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। पर्यटन, संस्कृति एवं लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के ढाई हजार से ज्यादा विदेशी पर्यटक छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए। उन्होंने बताया कि पर्यटकों से राज्य को 26 लाख से ज्यादा की आय हुई।

भाजपा सदस्य देवजी भाई पटेल के प्रश्नों के लिखित जवाब में श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2008-09 में प्रदेश में लगभग 11 सौ 47 एवं वर्ष 2009-10 में 1415 विदेशी पर्यटक आए। इन पर्यटकों से 2008-09 में 12 लाख 30 हजार 271 एवं वर्ष 2009-10 में 14 लाख 25 हजार 561 रुपए इस तरह कुल 26 लाख 55 हजार 832 रुपए की आय प्राप्त हुई। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें साउथ एशियन ट्रेवल ट्रेड एक्सचेंज नई दिल्ली, वर्ल्ड ट्रेवल मार्च लंदन, इंटरनेशनल ट्रेवल बोर्स बर्लिन, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बंगलुरू, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, हालीडे एक्सपो विशाखापटनम, नागपुर इंडिया ट्रेवल मार्ट जयपुर, गोवा, कास्मो ट्रेवल एंड टूरिज्म बिल्ड फेयर रायपुर, फेस्टिवल अंगुल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल टूरिज्म एंड फूड फेस्टिवल कोलकाता, ट्रेवल वर्ल्ड एमआईसीई एक्जीबिशन मुंबई, टाईम ट्रेवल फेयर मुंबई, अहमदाबाद, सेकंड विजन राजस्थान, जयपुर, एयर ट्रेवलर्स एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट विशाखापटनम, वर्ल्ड गोवा रोड शो आदि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय इवेन्ट्स में सहभागिता कर स्टाल के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रचार-प्रसार किया गया।

मंत्री ने बताया कि टूर ऑपरेटर्स एवं ट्रेवल एजेंट्स की कांफ्रेंस आयोजित कर विदेशी पर्यटकों को छत्तीसगढ़ राज्य में व्यक्तिगत एवं पैकेज टूर के माध्यम से भ्रमण पर भेजने हेतु प्रेरित किया गया। ट्रेवल राइट्र्स के साथ भी कांफ्रेंस आयोजित कर प्रदेश के पर्यटन स्थल के महत्व को दर्शाते हुए आलेख लिखने हेतु प्रोत्साहित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पत्र-पत्रिकाओं में पर्यटन स्थल से संबंधित लेख एवं विज्ञापन का प्रकाशन करवाया गया।

15 माह बाद भी एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन नहीं

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का मामला लटक गया है। मनोनीत सदस्य का पद 15 महीने से खाली पड़ा है। लगभग एक तिहाई कार्यकाल ऐसे ही निकल गया।

राज्य की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में एंग्लो इंडियन कोटे से एक सदस्य के मनोनयन का प्रावधान है। नियमों के मुताबिक विधानसभा के गठन के साथ ही सरकार के सुझाव पर सदस्य का मनोनयन किया जाता है। लेकिन नई विधानसभा के गठन के 15 महीने बाद भी एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन नहीं हो पाया है। इसके पहले दोनों बार सदस्य का मनोनयन 6 माह के भीतर ही कर दिया गया था। जोगी शासनकाल में बिलासपुर जिले की नेता इंग्रिड मैक्लॉउड को एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। इसी तरह मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की पहली पारी में सुश्री रोजलिन बेकमेन को सदस्य बनाया गया।

इस बार एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन के लिए सरकार और संगठन के नेता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में लगातार चुनावों के कारण इस पद पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के चलते ही निगम-मंडलों में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इसके बाद सरकार बजट सत्र में व्यस्त हो गई है। सत्र के निपटने के बाद निगम-मंडलों में नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अभी कुछ महीने और सदस्य का मनोनयन नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ मनोनीत सदस्य के लिए कई नेताओं की नजरें टिकी हुई है।

भाजपा नेता इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। संगठन के बड़े नेताओं का कहना है कि यह मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का मामला है। भाजपा के महामंत्री (संगठन) रामप्रताप सिंह का कहना है कि इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। यह संगठन का विषय नहीं है। इस पर चर्चा होने पर सदस्य के मनोनयन पर विचार किया जाएगा।

एएसआई में भर्ती के लिए 22 को परीक्षा

रायपुर, 18 मार्च। स्टेनोग्राफर-सूबेदार (अ) एवं सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद की भर्ती के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक नाप-जोख की तिथि 22 मार्च से 25 मार्च 2010 निर्धारित की गई है।

पुलिस अधीक्षक रेल व अध्यक्ष भर्ती समिति रायपुर ने बताया कि उम्मीदवारों का शारीरिक नाप-जोख जिला पुलिस लाईन पेंशनबाड़ा रायपुर में प्रात: नौ बजे से सम्पन्न किया जाएगा। शारीरिक नाप-जोख के पहले उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज की मूल प्रतियों की जांच की जाएगी। पुलिस अधीक्षक रेल ने समस्त उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल दस्तावेजों के साथ जिला पुलिस लाईन पेंशनबाड़ा रायपुर के परेड ग्राउण्ड में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने कहा है।

लोहिया जन्म शताब्दी पर 23 को आयोजन

रायपुर, 18 मार्च। प्रख्यात राजनीतिक चिन्तक डॉ. राममनोहर लोहिया की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 23 मार्च को शाम 4 बजे संस्कृति विभाग के सभागार में शताब्दी समारोह मनाया जाएगा।

कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, रामसुन्दर दास, उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री ओपी श्रीवास्तव तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रमुख वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरूषोत्तम लाल कौशिक एवं अधवक्ता चिन्तक कनक तिवारी भी मौजूद रहेंगे।

शहर-ग्रामीण अध्यक्ष के लिए जोड़तोड़

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 मार्च। भाजपा शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष के नामों को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। बताया गया है कि आरडीए के पूर्व अध्यक्ष श्याम बैस ने रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वहन करने में असमर्थता जाहिर कर दी है। जबकि शहर अध्यक्ष के लिए वर्धमान सुराना और नगर निगम के पूर्व सभापति रतन डागा के नामों की चर्चा है।

भाजपा में मंडल पदाधिकारियों के नामों पर सहमति बनाने की कोशिशें चल रही है। 25 मार्च तक रायपुर ग्रामीण और शहर के मंडलों के पदाधिकारी तय कर लिए जाएंगे। इसी कड़ी में शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष को लेकर चर्चा चल रही है। बताया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बैस के बड़े भाई श्याम बैस को रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा था। चर्चा है कि संगठन के प्रमुखों ने उनसे चर्चा भी की किंतु उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाने से साफ तौर पर मना कर दिया। श्याम बैस संगठन के बजाए किसी निगम मंडल में जगह पाने के लिए उत्सुक बताए जाते हैं।

**श्याम बैस की मनाही
शहर के लिए सुराना - डागा का नाम चर्चा में**

बैस की मनाही के बाद अब पलारी के डॉ. अजय राव के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। ज्यादातर नेता डॉ. राव के नाम पर सहमत बताए जाते हैं। इसके अलावा अनिमेश कश्यप का नाम भी चर्चा में है। उधर, रायपुर शहर अध्यक्ष पद के लिए वर्धमान सुराना और रतन डागा के बीच में फैसला होना है। डागा नगर निगम के सभापति रह चुके हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री के समर्थक माने जाते हैं। उनके नाम पर नगरीय प्रशासन मंत्री राजेश मूणत भी सहमत हैं। डागा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बैस सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सुराना बृजमोहन अग्रवाल का समर्थन बताया जाता है। महामंत्री संगठन राम प्रताप सिंह इस सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बैस और दोनों मंत्रियों के अलावा विधायक नंदकुमार साहू से चर्चा करेंगे।

इनमें से किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, पार्षद सुभाष तिवारी सहित कुछ अन्य लोगों का भी नाम भी चर्चा में है। मंडलों का चुनाव होने के बाद जिला अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।

खेतिहर मजदूरों को 100 रुपए प्रतिदिन वेतन देने आम सहमति

रायपुर, 18 मार्च। खेतिहर श्रमिकों को आगामी एक अप्रैल से कम से कम एक सौ रूपए प्रतिदिन वेतन मिलेगा। यह न्यूनतम वेतन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले ग्रामीणों को दिया जाएगा।

श्रम विभाग के प्रमुख सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में आयोजित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में इस विषय पर आम सहमति बनी है। सलाहकार बोर्ड की इस आम सहमति से प्रदेश के श्रम मंत्री चन्द्रशेखर साहू और मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह को अवगत कराया जाएगा। खेतिहर मजदूरों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले ग्रामीणों के वेतन का अंतिम निर्धारण मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर श्रम मंत्री द्वारा किया जाएगा। बैठक में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के सदस्य एस.के.राठौर, नरेश सिंह चौहान, नूतनेश्वर, डी.आर. महापात्रा सहित छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ के अध्यक्ष महेश कक्कड़, छत्तीसगढ़ सीमेंट निर्माता संघ के प्रतिनिधि रवि तिवारी भी उपस्थित थे। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी की ओर से आर.एस. सिंह और लघु उद्योग संघ की ओर से एस.के.मलानी ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त द्वय जागड़े और श्रीमती सविता मिश्रा भी शामिल हुए।

कामधेनू विश्वविद्यालय की घोषणा से गौ प्रेमियों में खुशी

रायपुर, 18 मार्च। कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू द्वारा विधानसभा में बहूप्रतिक्षित कामधेनू विश्वविद्यालय स्थापना दुर्ग जिले के अंजोरा में किए जाने की घोषणा से प्रदेश के समस्त गौप्रेमी धर्मावलम्बी संगठनों, भाजपा गौवंश विकास प्रकोष्ठ एवं गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है।

भाजपा गौवंश विकास प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री प्रेम सिंघानिया ने कहा कि प्रकोष्ठ द्वारा राज्य में कामधेनू विश्वविद्यालय की मांग शासन के समक्ष प्रमुखता से रखी थी जिसका यह सुखद परिणाम आया है गोधन राष्ट्रीय सम्पति है उसकी सुरक्षा एवं संवर्धन राष्ट्रीय दायित्व है गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था को पुर्नस्थापित करने गोबर-गौमूत्र का उद्योगीकरण करने, गोस्वास्थ्य का आधार है ऊर्जा का अखंड स्त्रोत है गौशालाओं को प्रोत्साहन व शोध कार्यों को बढ़ावा देने गौसंरक्षण, संवर्धन में किसानों महिलाओं युवकों की भागीदारी सुनिश्चित करने प्रशिक्षण संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला राज्य है श्री सिंघानिया ने कहा कि प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री का अभिनंदन किया जावेगा। महावीर गौशाला के अध्यक्ष रामजी लाल अग्रवाल ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में गोपालन को बढ़ावा मिलेगा। डॉ. हरिभाई जोशी, अचलदास पारख ने कहा कि ग्राम्य विकास व गौसंरक्षण में विश्वविद्यालय की स्थापना स्वागतेय है प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री श्री कुमार साहू जयप्रकाश पांडे, श्रीमती चित्ररेखा निर्मलकर, अरविंद देशपांडे, श्रीमती पुष्पा शर्मा, पंकज निर्मलकर, मोहनलाल साहू, जयंत सिंह, ने भी विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मार्कफेड के अध्यक्ष राधाकृष्ण गुप्ता ग्रामीण नागरिक सहकारी बैंक, अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेय प्रकोष्ठ के श्री ऋषि अग्रवाल डीएस अहलूवालिया जगदीश मिततल ने कहा कि गाय हम सबकी माता है शासन के इस घोषणा से गौहत्या पर अकुंश लगेगा वही वैज्ञानिक अनुसंधानों व नवीन पाठयक्रम से वन, वनस्पति एवं गौसम्पदा का हमारे जीवन में विशिष्ठ उपयोजन मूल्य भी है पता चलेगा।

फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने सलाहकार समिति गठित

रायपुर, 18 मार्च। राज्य शासन द्वारा फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य होंगे। यह समिति साधारणतया तीन वर्षों के लिए होगी, लेकिन राज्य शासन द्वारा समिति के कार्यकाल में एक वर्ष के लिए वृद्धि किया जा सकेगा।

समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग, सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी), मोहनचंद सुंदरानी रायपुर और विधायक देवजी भाई पटेल को सदस्य नामांकित किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) के सचिव समिति के संयोजक होंगे। शासन के समक्ष विचारार्थ जब किसी चलचित्र को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने के लिए आवेदन आएगा, उसी समय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। समिति का यह दायित्व होगा कि संबंधित चलचित्र को देखने के बाद सात दिनों के भीतर अनुशंसा वाणिज्यिक कर विभाग को भेजेगी।

समिति के सदस्यों को इस कार्य के लिए अलग से वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अशासकीय सदस्यों को प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान परिवहन और दैनिक भत्ते की पात्रता होगी। समिति किसी भी चलचित्र के पूर्वविलोकन के लिए किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति का मत लाभ लेकर मत बना सकेगी और राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकेगी। राज्य शासन द्वारा समिति से यह राय मांगी जा सकेगी कि कोई चलचित्र कलात्मक है अथवा नहीं।

साथ ही राज्य शासन समिति को चलचित्र संबंधी अन्य मसले भी परामर्श के लिए सौंप सकेगा। समिति के किसी भी ऐसे सदस्य को किसी भी चलचित्र के बारे में अनुशंसा करने का अधिकार नहीं होगा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप भाग लिया हो। समिति द्वारा कर मुक्ति के लिए उन्हीं चलचित्रों पर विचार किया जाएगा, जिनके लिए सेंसर बोर्ड के प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन किया गया है।

पदस्थापनाएं

रायपुर, 18 मार्च। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापनाएं की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तीन अलग-अगल आदेशों में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि डी.एस. मिश्र को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इसी तरह सचिव वित्त एवं आयुक्त सह-संचालक संस्थागत वित्त श्रीमती रेणु जी.पिल्ले की सेवाएं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली को संचालक, जनगणना, छत्तीसगढ़ के पद पर नियुक्ति के लिए पांच वर्ष के लिए सौंपी गई है।

आयुक्त आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम डॉ. बी.एस. अनंत को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उप सचिव, वित्त अविनाश चंपावत को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उप सचिव वाणिज्यिक कर विभाग और पदेन अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कॉमनवेल्थ-2010 की मशाल 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ में

रायपुर, 18 मार्च। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 19वें कामनवेल्थ प्रतियोगिता-2010 के संबंध में राज्य शासन द्वारा रायपुर जिले की आयोजन उप समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन (खेल एवं युवा कल्याण) द्वारा आयोजन की संभावित रूप रेखा का निर्धारण किया गया है, जिसे अंतिम रूप देने के लिए उप समिति के सदस्यों की बैठक शुक्रवार 19 मार्च को अपरान्ह 3.15 बजे यहां कलेक्टोरेट के सभागृह में आयोजित की जाएगी।

आयोजन उप समिति की बैठक 19 मार्च को

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में 19वें कामनवेल्थ गेम 2010 का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मशाल चीन बैटन लंदन से चलकर विभिन्न देशों सहित भारत के विभिन्न राज्यों से होते हुए आगामी आठ अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आ रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन को राज्य की गरिमा के अनुरूप आयोजित करने हेतु राज्य शासन द्वारा रायपुर जिले की आयोजन उप समिति का गठन किया गया है। इस बैठक में बैटन रिले मार्ग का तथा मार्ग पर पड़ने वाले लगभग 12 चौक पर अतिथियों का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा चौक पर मंच निर्माण, मंच पर खेल संघों और संस्थाओं की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक चौक पर और मार्ग पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैटनधारक खिलाड़ी, रिले मोड़, स्कूली बच्चों की प्रत्येक चौक पर उपस्थिति और उनके प्रभारियों की नियुक्ति सहित विभिन्न जरूरी गतिविधियों के लिए संबंधितों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।